गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 213
दि. 04.12.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन, 12 माओवादी ढेर, 3 जवान शहीद

(जीएनएस)। बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बुधवार सुबह हुई भीषण मुठभेड़ ने पूरे पश्चिम बस्तर डिवीजन में तनाव पैदा कर दिया। इस मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सली मारे गए हैं, जबकि सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए और एक अन्य घायल हुआ। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर की गई।

पुलिस और केंद्रीय बलों की ज्वाइंट टीम ने बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा के वेस्ट बस्तर डिवीजन के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। घेराबंदी के दौरान नक्सलियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी), स्पेशल टास्क फोर्स और CoBRA यूनिट की टीम शामिल थी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घात लगाए नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। शहीद जवानों में प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी, आरक्षक दुकारू गोंडे और जवान रमेश सोड़ी शामिल हैं। डीआरजी के 2 अन्य जवान घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुठभेड़ स्थल से कुल 12 नक्सलियों की लाशें बरामद की गई हैं और SLR, INSAS तथा .303 राइफलें भी कब्जे में ली गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि बीजापुर जिले में पश्चिम बस्तर डिवीजन के जंगलों में नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों के संबंध में खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को कार्रवाई के लिए रवाना किया गया था। मुठभेड़ के तुरंत बाद अतिरिक्त बल भी मौके पर भेजे गए ताकि किसी भी बची हुई नक्सली गतिविधि को तुरंत रोका जा सके।

साल 2025 में अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 275 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 239 माओवादी बस्तर डिवीजन में मारे गए हैं, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा समेत सात जिले शामिल हैं। वहीं रायपुर डिवीजन के गरियाबंद जिले में 27 और दुर्ग डिवीजन के मोहला-मानपुर और अंबागढ़ चौकी जिले में 2-2 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि इस साल के इन ऑपरेशनों से नक्सलियों की घुसपैठ और हमला करने की क्षमता में गंभीर नुकसान हुआ है। बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र अब भी संवेदनशील माना जाता है, और सुरक्षा बल लगातार सर्च और निगरानी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन पूरी तरह समाप्त होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी, ताकि नागरिक सुरक्षा और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति स्पष्ट हो।

सुमात्रा में हाहाकार: 712 मौतों के बाद भी थमा नहीं विनाश, गांवों के गांव बह गए, लोग मदद की आस में आसमान तक रहे हैं

(जीएनएस)। जकार्ता। मानो प्रकृति ने दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के तटों पर लगातार अपना क्रोध उंडेलने का निर्णय ले लिया हो। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा की तबाही से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप तो जैसे और भी भयावह प्रहार झेलने को मजबूर हो गया। समुद्र से उठे तूफान और आसमान से बरसे अनियंत्रित जलप्रलय ने मिलकर जो दृश्य रचा, वह मानवीय त्रासदियों की सबसे काली तस्वीर जैसा है। आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि अब तक 712 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 402 से अधिक लोग लापता हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की मानें तो यह वास्तविक संख्या का केवल अनुमान है—अभी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पहुँच तक नहीं हो पाई है, और जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वहाँ कितने लोग बचे हैं।

उत्तरी सुमात्रा, पश्चिमी सुमात्रा और आचे प्रांत इस कहर की सबसे भयानक मार झेल रहे हैं। कहीं कंकाल बन चुकी सड़कें हैं, कहीं पहाड़ों से टूटकर गिरे मिट्टी के विशाल ढेर पूरे-के-पूरे बस्तियों को निगल चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार जो हुआ वह सामान्य चक्रवाती गतिविधि नहीं थी।

दो दुर्लभ उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक-दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आ गए, और नतीजा यह हुआ कि सुमात्रा के तटीय और पर्वतीय इलाकों पर 24 घंटे से कम समय में इतनी बारिश हुई कि दशकों के रिकॉर्ड चकनाचूर हो गए।

बाढ़ का पानी जब पहाड़ों को छूते हुए नीचे उतरा, तो अपने साथ चट्टानें, पेड़ और पूरा-पूरा मलबा समेटता चला गया। कई गांव एक पल में मिट्टी की नदियों में बदल गए। घर, खलिहान, मस्जिदें, स्कूल—सब कुछ मलबे में समा गया। हजारों परिवारों के घर समुद्र में बह चुके हैं। बच्चे अपने माता-पिता को ढूंढ रहे हैं, माता-पिता अपने खोए बच्चों की तलाश में राहत शिविरों के हर चेहरे को बार-बार देखते हैं। हर जगह एक ही किस्म का मौन, एक ही किस्म की व्याकुलता और एक ही सवाल—"अब आगे जीवन कैसे चलेगा?"

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी, इंडोनेशियाई सेना, पुलिस और हजारों स्वयंसेवक राहत कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन कई इलाकों में हालात इतने विकट हैं कि बचाव दलों को वहां तक पहुंचने में कई दिन लग रहे हैं। कई पुल बाढ़ के साथ बह गए हैं और सड़कें टूटकर नदी बन चुकी हैं। जिन गांवों तक पहुंचना संभव हुआ है, वहां लोग न पीने का साफ पानी पा रहे हैं और ना खाना। कई लोग केवल बारिश के पानी और टूटे घरों की छतों पर बचे कुछ सूखे सामान के सहारे जिंदा हैं। यह दृश्य दिल दहलाने वाला है।

आचे प्रांत के गवर्नर मुजाकिर मनाफ ने जब मीडिया से बात की, तो उनकी आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने बताया कि कुछ गांव सात दिनों से किसी संपर्क में नहीं हैं और वहाँ फंसे लोग मानो दुनिया द्वारा भुला दिए गए हों। उन्होंने कहा, "हमारे पास साधन नहीं हैं। हमारी मशीनें नाकाम हो चुकी हैं। हमें तुरंत केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहायता की जरूरत है।" यह बयान जितना राजनीतिक था, उससे कहीं अधिक मानव पीड़ा की पुकार जैसा था।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भी माना है कि संकट अत्यधिक बड़ा है और राहत प्रयासों को कई गुना तेज करने की जरूरत है। हेलीकॉप्टरों से भोजन गिराया जा रहा है, नावों के जरिए नदी के मार्ग से गांवों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रकृति के इस कहर ने जिस पैमाने पर विनाश किया है, वह किसी एक देश के लिए अकेले संभालना कठिन हो गया है।

सुमात्रा के लोग कहते हैं कि उन्होंने कई तूफान देखे हैं, कई बार बाढ़ का पानी गांवों तक पहुंचा है, लेकिन इस बार जो हुआ वह किसी भी 'सामान्य आपदा' की परिभाषा को पार कर गया है। लोग बताते हैं कि रात भर आसमान गरजता रहा, बारिश ऐसी बरसी जैसे बादल फट गया हो, और भोर होने तक गाँवों के नक्शे बदल चुके थे। जिन घरों में कल शाम खाना पक रहा था, आज वहां केवल कीचड़ है—और कीचड़ के बीच फंसी टूटी हुई जिंदगियाँ।

पांच घंटे का कूटनीतिक मैराथन भी बेअसर: पुतिन–ट्रंप दूतों की वार्ता ठंडी पड़ी, यूक्रेन शांति का रास्ता और उलझा

(जीएनएस)। मास्को। यूक्रेन युद्ध को रोकने की उम्मीद में जो बातचीत दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी, वह पाँच घंटे तक चला एक लंबा कूटनीतिक मैराथन बनकर रह गई—लेकिन बिना किसी ठोस नतीजे के। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मास्को से वापस लौट रहे हैं, लेकिन न उनके हाथ कोई समझौता आया, न युद्ध विराम की कोई आशा मजबूत हो सकी। जिस शांति प्रस्ताव को लेकर वे आए थे, वह रूस की अपेक्षाओं से मेल नहीं खा पाया और दुनिया के सबसे घातक युद्धों में से एक अपनी दिशा बदले बिना आगे बढ़ता दिख रहा है।

बैठक का माहौल शुरू में उम्मीदों से भरा था। दोनों देशों के प्रतिनिधि एक ही मेज पर बैठे थे, और यह मान लिया गया था कि शायद लंबे समय बाद वाशिंगटन और मॉस्को यूक्रेन को लेकर किसी कम से कम 'रुकावट' वाली मंज़िल की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जैसे-जैसे घंटे बीतते गए, यह स्पष्ट होने लगा कि दोनों पक्षों के बीच खाई उतनी ही गहरी है जितनी पिछले दो वर्षों में बनी है। पुतिन के वरिष्ठ सलाहकार यूरी उशाकोव ने बैठक के बाद जो बयान दिया, वह पूरी वार्ता की हताश तस्वीर को बयान करने के लिए पर्याप्त था।

उशाकोव ने स्वीकार किया कि बातचीत "उपयोगी" थी — यानी माहौल विनम्र रहा, भाषा नरम रही — लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि यह "अधूरी" रही। उनके इस एक शब्द ने साफ कर दिया कि बातचीत का वास्तविक लक्ष्य—यूक्रेन में युद्ध रोकने की दिशा में निर्णायक आगे बढ़ना—अभी बहुत दूर है। उन्होंने यह भी कहा कि "यूक्रेन संकट के समाधान के हम करीब नहीं पहुंचे हैं। अभी बहुत काम किया जाना बाकी है।" यह वाक्य वही है, जो दो वर्षों से दुनिया हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुनती आई है।

अमेरिकी दूतों ने रूस को ट्रंप की 28 सूत्रीय योजना के अलावा चार और गोपनीय दस्तावेज सौंपे, जिनकी सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई। यह गोपनीयता कई सवाल भी खड़े करती है — क्या इन दस्तावेजों में यूक्रेन की जमीन, नाटो विस्तार, रूस की सुरक्षा चिंताएँ, या पश्चिमी प्रतिबंधों पर छूट जैसी संवेदनशील बातें शामिल हैं? अब तक यह केवल अनुमान हैं, क्योंकि दोनों देशों ने तय किया है कि इन दस्तावेजों और बातचीत के सबसे अहम हिस्सों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि दोनों पक्ष अभी किसी ठोस, खुले और पारदर्शी समझौते के लिए तैयार नहीं दिख रहे। वार्ता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि रूस और अमेरिका उन क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा तक नहीं कर सके, जिन्हें इस युद्ध का मूल माना जाता है। पूर्वी यूक्रेन, क्रीमिया, डोनबास, सुरक्षा गारंटी जैसे विषय ही इस संघर्ष के केंद्र में हैं, लेकिन इन्हीं पर बातचीत नहीं हो पाई। कूटनीति में जब सबसे आवश्यक विषयों पर चुप्पी रह जाए, तो बातचीत का अर्थ अधिकतर प्रतीकात्मक ही रह जाता है—और इस बैठक में भी वही हुआ।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि फिलहाल पुतिन और ट्रंप के बीच किसी भी सीधी बातचीत की कोई योजना नहीं है। कुछ विश्लेषकों को उम्मीद थी कि इस बैठक के बाद शायद दोनों नेताओं के बीच किसी वीडियो लिंक या तृतीय देश में शिखर वार्ता का रास्ता खुलेगा, लेकिन रूस ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई योजना फिलहाल एजेंडा में नहीं है। इसका मतलब यह है कि अभी समाधान की बजाय संवाद का प्रयास ही पहली सीढ़ी पर अटका हुआ है। हालाँकि, पुतिन ने विटकॉफ और कुशनर के माध्यम से ट्रंप तक कुछ "महत्वपूर्ण संदेश" भेजे हैं। यह संदेश क्या हैं — यह भी गोपनीय रखा गया है। अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन लौटकर इन बातों को ट्रंप के सामने रखेगा और उनके निर्देश के बाद ही अमेरिका की अगली प्रतिक्रिया मास्को भेजी जाएगी। इससे यह भी साफ झलकता है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर भी यूक्रेन को लेकर आगे क्या लाइन ली जाए, इस पर अभी पूर्ण स्पष्टता नहीं है।

यूक्रेन युद्ध पहले ही यूरोप की सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया की सामरिक राजनीति को अस्थिर कर चुका है। हर दिन, हर हफ्ते इस संघर्ष में नए हमले, नई मौतें और नई बर्बादी जुड़ रही है।

दस साल बाद फिर जग उठीं उम्मीदें : MH370 की तलाश 30 दिसंबर से नए अभियान के साथ शुरू, गहरे समुद्र की खामोशी में जवाब खोजने उतरेगी टीम

(जीएनएस)। कुआलालंपुर। दुनिया के विमानन इतिहास में ऐसा शायद ही कोई हादसा होगा जिसने लोगों की स्मृतियों में इतना गहरा घाव छोड़ा हो, जितना 2014 में लापता हुए मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH370 ने छोड़ा था। जैसे हवा में घुलकर गायब हो गया एक बोइंग 777, जैसे आकाश और सागर के बीच किसी ने उसकी कहानी चुरा ली हो। और उस दिन के बाद से दुनिया भर में लाखों लोगों के मन में केवल एक ही सवाल जड़ की तरह पैठ गया—आखिर उस विमान का हुआ क्या? अब, लगभग एक दशक बाद, मलेशिया सरकार ने घोषणा की है कि MH370 की खोज एक बार फिर से शुरू होगी और 30 दिसंबर से समुद्र की अथाह गहराइयों में एक नया अभियान चलेगा, मानो मौन पड़े महासागर से एक बार फिर सत्य का पीछा किया जा रहा हो।

मलेशियाई परिवहन मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस अभियान की जिम्मेदारी अमेरिकी समुद्री खोज विशेषज्ञ कंपनी ओशन इनफिनिटी को सौंपी गई है। कंपनी की तकनीकी टीम 55 दिनों तक लगातार उस समुद्री इलाके में अत्याधुनिक पनडुब्बी उपकरणों के साथ खोज चलाएगी, जिसे विशेषज्ञ वर्षों से सबसे संभावित क्षेत्र बताते रहे हैं। इस अभियान के लिए ओशन इनफिनिटी और मलेशिया सरकार के बीच पिछले मार्च में एक विशेष समझौता हुआ था, जिसके अनुसार यदि कंपनी को कोई ठोस सबूत या मलबा नहीं मिलता, तो सरकार को भुगतान नहीं करना होगा। यह

व्यवस्था इस बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन को और भी अधिक परिणाम केंद्रित बनाती है।

2014 की उस मनहूस सुबह को याद करते ही आज भी अनगिनत परिवारों का दिल सिहर उठता है। 8 मार्च 2014 को MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 227 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें जीवन की हजारों कहानियाँ, सपने, उम्मीदें और भविष्य की असंख्य योजनाएँ थीं। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही अचानक विमान रडार से गायब हो गया। न कोई अंतिम संदेश, न कोई SOS, न किसी तरह की चेतावनी—बस एक पल में विशाल आकाश में एक विशाल विमान का लापता हो जाना। यह घटना इतनी असामान्य थी कि दुनिया भर के विशेषज्ञ शुरू में ही दिग्भ्रमित हो गए। जांचों ने अनगिनत सिद्धांत सुर्खियों में लाए—तकनीकी खराबी, पायलट की असामान्य हरकतें, इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी, यहाँ तक कि आतंकवादी कार्रवाई—लेकिन किसी भी सिद्धांत को पुष्ट करने वाला प्रमाण कभी नहीं मिला। जैसे विमान जमीन पर उतरा ही न हो, जैसे सागर ने उसे निगलकर उसकी हर याद मिटा दी हो। 2018 में मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर दक्षिणी हिंद महासागर के बड़े हिस्से में व्यापक खोज अभियान चलाया। उस दौरान महासागर के नीचे हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्कैन किए गए। कुछ संभावित जगहें चिन्हित भी की गईं, परंतु कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। कई महीनों की मेहनत, अरबों डॉलर की लागत और अनगिनत उम्मीदों के बाद अभियान रोकना पड़ा और दुनिया को लगा कि यह रहस्य कभी नहीं सुलझ सकेगा। लेकिन पीड़ित परिवारों ने हार नहीं मानी। उनका कहना था कि जब तक एक भी संभावना जीवित है, तब तक खोज का प्रयास रुकना नहीं चाहिए। इसी ज़िद, दर्द और उम्मीद के मिश्रण ने मलेशियाई सरकार को एक बार फिर इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अब, जब 30 दिसंबर से समुद्र की गहराई में दोबारा अभियान शुरू होगा, तो केवल मलेशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिक जाएँगी। कई वर्ष बीत चुके हैं, समुद्र की धाराएँ बदल चुकी हैं, समय ने अनगिनत निशान मिटा दिए होंगे, लेकिन फिर भी विज्ञान, तकनीक और मानवीय दृढ़ता का यह संयुक्त प्रयास एक बार फिर उस अनुत्तरित प्रश्न की ओर बढ़ रहा है कि आखिर MH370 के साथ वह अनहोनी क्या घटी थी जिसने उसे इतिहास का सबसे रहस्यमय विमान हादसा बना दिया। यह नया अभियान न केवल तकनीकी चुनौती है, बल्कि उन परिवारों की टूटती उम्मीदों को संभालने का प्रयास भी है, जो वर्ष दर वर्ष अपने प्रियजनों की वापसी का इंतजार करते रहे, या कम से कम उस सत्य का, जो उन्हें मानसिक रूप से बंद दरवाजों से बाहर आने का रास्ता दे सके। यदि इस बार खोज में कोई सुराग मिलता है, कोई मलबा, कोई टुकड़ा, कोई संकेत—तो न केवल यह रहस्य सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम होगा, बल्कि दुनिया के अन्य विमानन हादसों की जांचों को भी नया आधार मिलेगा।

MH370 की खोज फिर शुरू होने का यह फैसला एक प्रतीक है—आशा के न बुझने का, विज्ञान के आगे बढ़ते रहने का, और उन सवालों के जवाब ढूँढने के संकल्प का जिनके साये वर्षों से मानवता को परेशान करते रहे हैं। अब सबकी निगाहें उस विशाल महासागर पर हैं, जो शायद 10 साल बाद अपने मौन में छिपी कहानी को बयां करने के लिए तैयार हो रहा है।

संपादकीय

डिजिटल अरेस्ट

यह विडंबना है कि जब तक देश में कथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अनुमानित तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक ठगी की जा चुकी है, कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी मुहिम शुरू हो पा रही है। वह भी सरकार के बजाय शीर्ष अदालत की पहल पर। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करे, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर ठगों के खाते फ्रीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दायरा भारत से बाहर की सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है। दुखद है कि साइबर अरेस्ट के मामलों में सबसे अधिक निशाना बुजुर्गों को ही बनाया जाता है, जिन्हें डिजिटल लेन-देन की गंभीर जानकारी नहीं होती। बुजुर्गों को निशाना बनाने का यह प्रतिशत 78 से 82 फीसदी बताया जाता है। कई जगह यह प्रतिशत 99 फीसदी तक है। वहीं जनवरी से अप्रैल 2024 में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के 46 फीसदी मामलों के तार म्यांमार,कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़े रहे हैं। निस्संदेह, हाल के वर्षों में डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध के सबसे कुटिल रूप में बनकर उभरी है। यह अपराध न केवल देश की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये, बल्कि कानून प्रवर्तन तंत्र में जनता के विश्वास के लिये भी बड़ा खतरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन घोटालों की देशव्यापी जांच सीबीआई को सौंपने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समय के अनुरूप सार्थक हस्तक्षेप है। इसी क्रम में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिये सीबीआई को सहमति दें।

दरअसल, न्यायालय ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि साइबर अपराधी राज्यों की सीमाओं का लाभ उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर टुकड़ों-टुकड़ों में जांच सीमा-पार के साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बढ़ावा देती है। दरअसल, साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट के जरिये भोले-भाले लोगों व बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। वे कानून प्रवर्तन अधिकारी या जज बनकर मोटी रकम देने के लिये उन्हें आतंकित करते हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति से एक करोड़ रुपये की ठगी के बाद अदालत ने इस व्यापक समस्या का स्वतः संज्ञान लिया। उन्हें धमकाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेशों का इस्तेमाल किया गया। यह बेहद परेशान करने वाली स्थिति है कि साइबर अपराधी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल रहे हैं। तभी शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है, देश की केंद्रीय एजेंसी को इस मामले की तह तक तुरंत पहुंचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने की पूरी छूट दी गई है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच का अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा दूरसंचार विभाग को भी सिम कार्ड के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिये कहा गया है। निश्चित रूप से कोर्ट की सार्थक पहल के बाद यदि ये सभी उपाय सिरे चढ़ते हैं तो इस गंभीर अपराध के खिलाफ एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दे पाना संभव होगा। कोर्ट ने विश्वास जताया है कि केंद्रीय एजेंसी बिना किसी भय या पक्षपात के जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। इसमें राज्य सरकारों की सक्रियता व सजगता भी सीबीआई को अपराध की तह तक पहुंचने में मददगार सबित हो सकती है। यह भी जरूरी है कि एजेंसी की कार्रवाई में लालफीताशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। इसके साथ ही नागरिकों को भी ऐसे अपराधों के प्रति सजग रहना होगा। जागरूकता-सतर्कता उन्हें अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचा सकती है। ऐसी किसी कॉल के आने पर उन्हें रुककर विचार करना चाहिए और हड़बड़ी में बैंक से जुड़ी कोई जानकारी देने से बचना चाहिए।

मेजर पॉवर बड़ी उपलब्धि तो सुपर पॉवर बनना बड़ी चुनौती

> ऑपरेशन सिन्दूर, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती साख, सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी भारत की ताकत बन गई है। भारत के साथ सबसे बड़ी ताकत स्थिर और कड़े निर्णय लेने में भी सक्षम सरकार होना एक सकारात्मक पक्ष है तो दूसरी और जेन जेड और उसके बाद की जैनरेशन की बड़ी भूमिका हो गई है।

आस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्था द्वारा जारी एशिया पॉवर इंडेक्स 2025 में भारत का मेजर पॉवर का दर्जा हासिल करना इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत शक्तिशाली देशों की कतार में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। लोवी द्वारा जारी इंडेक्स में मेजर पॉवर का दर्जा हासिल करने वाला भारत एक मात्र देश है जबकि सुपर पॉवर के रुप में अमेरिका और चीन अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। हांलाकि भारत ने मेजर पॉवर का दर्जा हासिल कर लिया है पर सुपर पॉवर का दर्जा हासिल करने में अभी भारत को लंबा समय और कड़ी मेहनत व प्रयास करने होंगे। दरअसल 8 पेरामीटर्स में 100 में से 70 से अधिक अंक अर्जित करने वाले देश ही सुपर पॉवर की श्रेणी में आते हैं और अमेरिका इसमें 80.5 अंक प्राप्त कर सुपर पॉवर बना हुआ है वहीं चीन भी अमेरिका के पीछे पीछे 73.7 अंकों के साथ दूसरा सुपर पॉवर बना हुआ है। हांलाकि डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका ने बहुत कुछ खोया है पर फिर भी पहला स्थान का ताज आने वाले सालों में भी छिनता हुआ नहीं लगता है। भारत ने अवश्य जापान को पछाड़ कर तीसरा स्थान बनाया है और 40 अंक प्राप्त कर मेजर पॉवर तो बन ही गया है। 40 या 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले देश मेजर पॉवर की श्रेणी में आते हैं और यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत अकेला देश बन गया है। एशिया प्रशांत के 27 देशों से शेष 23 देश मिडिल पॉवर व उससे नीचे की श्रेणी में हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस इंडेक्स में पहले दस में भी स्थान नहीं बना पाया है। पाकिस्तान सूची में 16 वें स्थान पर रहा है। निश्चित रुप से यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धी और इंटरनेशनल जगत में भारत के बढ़ते दबदबे का स्पष्ट संकेत है। ऑपरेशन सिन्दुर और इससे पहले भी जिस तरह से भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की अग्रगामी भूमिका तय की गई है उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। आर्थिक क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों ने इसे तीसरे पायदान पर लाने में खासी भूमिका तय की है। भारत आज दुनिया के देशों में बड़ी आर्थिक शक्ति के रुप में उभरा है और दुनिया के देशों में सबसे अधिक यानी कि विदेशी निवेश में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी द्वारा 2018 से एशिया पॉवर इंडेक्स जारी करना आरंभ किया है। 2025 में एशिया पॉवर इंडेक्स का सातवां संस्करण जारी किया है। लोवी द्वारा 8 पेरामीटर्स के आधार पर अंक जारी किये जाते हैं। इसमें सैन्य क्षमता, रक्षा नेटवर्क, आर्थिक शक्ति, अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध, कूटनीतिक व सांस्कृतिक संबंध, लचीलापन, भविष्य के संसाधन आदि पेरामीटर्स के आधार पर 27 देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑपरेशन सिन्दुर ने भारत की सैन्य शक्ति और ताकत से दुनिया के देशों को झकझोर कर रख दिया है। सैन्य संसाधनों में आज भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से भारत की इकोनोमी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है उससे दुनिया के देशों में भारत ने अलग ही स्थान अर्जित कर लिया है। भारत में देसी-विदेशी विदेशी निवेश का जिस तरह का माहौल बना है और जिस तेजी से विपरीत वैश्विक हालातों के बावजूद और यहां तक कि ट्रंप की टैरिफ नीति के बावजूद भारत की अर्थ व्वस्था व विकास का स्तर लगातार बने रहना बड़ी उपलब्धि है।

ऑपरेशन सिन्दूर, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती साख, सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी भारत की ताकत बन गई है। भारत के साथ सबसे बड़ी ताकत स्थिर और कड़े निर्णय लेने में भी सक्षम सरकार होना एक सकारात्मक पक्ष है तो दूसरी और जेन जेड और उसके बाद की जैनरेशन की बड़ी भूमिका हो गई है। आज तकनीकी रुप से भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत युवाओं का देश हो गया है। सैन्य क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव, इकोनोमिक क्षमता और प्रौद्योगिकी, डिजिटलाइजेशन, कूटनीतिक और सांस्कृतिक रिलेशन आदि क्षेत्र में भारत ने पिछले साल की तुलना में अधिक अंक अर्जित किये हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का वैश्विक स्तर पर आत्मविश्वास बढ़ा है और इसी का परिणाम है कि भारत आज आंख से आंख मिलाकर बात करने और आंतरिक व बाहरी निर्णय लेने में सक्षम और स्वतंत्र देश के रुप में उभरा है। हालांकि भारत के सामने अभी चुनौतियां भी बहुत है। सबसे बड़ी चुनौती जो विषय से अलग हटकर है वह है हमारे ही लोगों द्वारा विदेशी मीडिया व विदेशी धरती पर देश की छवि खराब करना है। होना यह चाहिए कि लाख राजनीतिक मतभेदों के बावजूद विदेश की धरती पर एक रहना और एक रहने का संदेश देना जरुरी हो जाता है। रक्षा नेटवर्क को और अधिक विस्तारित करने की चुनौती के साथ ही कूटनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अमेरिका की ट्रंप की देशी विदेशी नीति के कारण अमेरिका के अंकों में गिरावट दर्ज की गई है। देखा जाए तो भारत की सैन्य क्षमता के साथ साथ इकोनोमी के क्षेत्र में क्षमता का तेजी से विकास हुआ है। हांलाकि रक्षा नेटवर्क के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना है।

एशिया पॉवर इंडेक्स 2025 में भारत का मेजर पॉवर बनना और तीसरा स्थान बनाना भारत की दुनिया के देषों में बढ़ती साख का परिचायक है। निश्चित रुप से यह बड़ी उपलब्धि है पर अब भारत को इसे बनाये रखने और अन्य पेरामीटर्स के क्षेत्र में भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। चुनौतियां बहुत है पर चुनौतियों से पार पाते हुए ही कुछ अधिक अर्जित करना बड़ी बात हो जाती है। मेजर पॉवर से सुपर पॉवर बनना बड़ी चुनौती है पर सकारात्मक प्रयासों से सुपर पॉवर बनने के लक्ष्य के साथ ही भारत को आगे बढ़ना होगा।

प्रेरणा

जब माइक बन गया महायुद्ध का ब्रह्मास्त्र और कवि बन गए योद्धा

मिसिरबाबू, आपको जितनी बधाइयाँ दी जाएँ, कम हैं। सच कहूँ तो आपको किसी राष्ट्रीय पुरस्कार से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस महाआपदा से आप इस बार सकुशल बच निकले हैं, वह सामान्य मनुष्यों का खेल नहीं। कवि-सम्मेलन का युद्ध—हाँ, युद्ध! यह वह जगह है जहाँ कविता का जन्म कम, और कवियों का सर्वनाश अधिक होता है। आपने जिस रणभूमि को पीछे छोड़ दिया, वह महाभारत की पुनरावृत्ति है—बस फर्क इतना कि वहाँ तीर-कमान चलते थे और यहाँ शब्दों के बाण, ट्रोलों के गोले और तालियों के परमाणु बम चलते हैं। कभी कविता वह साधना थी जिसमें कवि अपने भीतर उतरकर शब्द का सृजन करता था। वह रात के तीसरे पहर जागता था, जैसे कोई साधक प्रार्थना के लिए जागता है। लेकिन आज का कवि? वह मंच पर ऐसे चढ़ता है जैसे चुनाव में टिकट काटने जा रहा हो। कविता की पंक्तियाँ कम, नारेबाज़ी ज़्यादा। गंभीरता कम, फूहड़पन अधिक। मंच पर नाच कम, परन्तु हाथ-पैर हवा में उड़ाकर देशभक्ति का नाटकीय प्रदर्शन भरपूर। श्रोता तालियों का ठेका लेकर आते हैं—जैसे ठहाके पर आज 50% छूट हो।

महल्ले के शर्मा जी, जिनके घर में पहले निराला, बच्चन, दिनकर और धर्मवीर भारती के ग्रंथ रखे थे, अब उन किताबों पर धूल चढ़ चुकी है। वे कवि-सम्मेलन का टिकट इसलिए खरीदते हैं कि वह सिनेमा से सस्ता है और पेट पकड़कर हँसने का मौका ज्यादा मिलता है। अब कविता की गहराई नहीं पूछी जाती—अब पूछा जाता है कि "भाई, आपने कितनी तालियाँ बटोरी?" जैसे कविता नहीं, कोई क्रिकेट मैच हो जिसमें रन गिने जा रहे हों।

इस मंचीय पागलपन का असर पृथ्वी से निकलकर यमलोक तक फैल चुका है। चित्रगुप्त जी के 'पुण्य-पाप अल्गोरिद्म' में पिछले दिनों अजीब खामियाँ आने लगीं। यमराज ने कहा—"चित्रगुप्त, यह क्या हो रहा है? पहले कविताएँ लिखने वाले पुण्यवान होते थे, अब इन सबके खाते में 'मंच पर फिसड्डी', 'तालियाँ कम', और 'हूटींग अधिक' जैसे अपराध दर्ज क्यों हैं?"

चित्रगुप्त ने अपना माथा पकड़ लिया—"प्रभु, अब पुण्य कविता की गहराई से नहीं, तालियों की संख्या से तय होता है। जो कवि मंच पर चिल्लाकर जनता को प्रभावित कर ले, वह पुण्यात्मा। और जिसने कविता लिखी लेकिन मंच पर नहीं पढ़ी, उसके खाते में 'संन्यासी किस्म का पाप' दर्ज कर दिया जाता है। अब कविता लिखने वाले सीधे स्वर्ग नहीं जाते—पहले उन्हें मंच पर साबित करना पड़ता है कि वे मनोरंजन कर सकते हैं।"

कवि-सम्मेलन का यह महायुद्ध लोगों को चोट नहीं पहुँचाता, लेकिन आत्मसम्मान को हड्डियों की तरह तोड़ देता है। यहाँ तलवारें नहीं चलतीं—'फ्लॉप' और 'घटिया कवि' की टिप्पणियाँ चलती हैं। खून नहीं बहता—सम्मान बहता है। कवि कवि का दोस्त नहीं; हर कवि दूसरे कवि को पछाड़ने आया है। संयोजक कवि के संदेश पढ़कर भी 'सीन ज़ोन' में छोड़ देता है। कवि संयोजक को अनफॉलो कर देता है। और जिस कवि ने एक बार मंच पर भीड़ को गुदगुदा दिया, वह पाँच मिनट बाद "महाकवि" बनकर घूमता है—चाहे उसकी कविता में व्याकरण भी गश्त मारता दिखे।

इस युद्ध की असली ताकत वे लोग हैं जो मोबाइल लेकर मंच के नीचे बैठते हैं। वे न न्यायाधीश हैं, न साहित्यकार—लेकिन उनकी उंगलियों में "ट्रेंड" का साम्राज्य है। वे तय करते हैं कि कौन कवि वायरल होगा और कौन गुमनाम मर जाएगा। अगर कवि ने गंभीर कविता पढ़ दी तो उसे 'बोरिंग' का तमगा मिल जाता है। और अगर मंच पर फूहड़ चुटकुला सुना दिया, तो वह "फ़ेसबुक स्टार", "इंस्टा आइकन" और "रेलगाड़ी जैसा रील मास्टर" बन जाता है।

पर सबसे बड़ा रहस्य यह है—मिसिरबाबू, आप इतने दिनों से इस महायुद्ध से कैसे बचते चले आ रहे हैं? सरकारें बदल जाएँगी, लेकिन यह मंचीय दबाव नहीं। कौन जाने कल कोई नया अध्यादेश आ जाए—"एक देश, एक कविता शैली", "कविता-पाठ अनिवार्य", "नागरिकता प्रमाणित करने हेतु कम-से-कम पाँच तालियाँ लाना आवश्यक"। शायद राशन कार्ड, पेंशन, आधार—सब आपके मंचीय प्रदर्शन से जुड़ जाएँ।

कल्पना कीजिए, एक दिन सरकारी अधिकारी आपकी खिड़की खटखटा कर पूछे—

"आपने आख़िरी बार कहाँ कविता पढ़ी?"

आप कहें—"मैं तो कविता अपने लिए लिखता हूँ।"

वह अधिकारी आपको इस तरह देखे जैसे आपने किसी राष्ट्रीय नीति का उल्लंघन कर दिया हो।

आपका शांत, निर्बाध, और बिना तालियों वाला कविता संग्रह तब किसी पुरातन ग्रंथ की तरह माना जाएगा—"ये किताबें उस जमाने की हैं जब कविता, कविता हुआ करती थी, स्टेज-शो नहीं।"

मिसिरबाबू, आपके बचने की वजह सिर्फ यह है कि आप अभी तक इस मंचीय 'कविता सरकस' में शामिल नहीं हुए। लेकिन याद रखिए, यह युद्ध रुकने वाला नहीं। हर दिन एक कवि किसी मंच पर मिटता है। हर दिन कविता की एक और लाश दफन होती है—कभी बेवकूफी की तालियों के नीचे, कभी हँसी के शोर में, कभी ठहाकों के आतंक में।

फिलहाल बधाई स्वीकार कीजिए। आप बच गए हैं।

लेकिन युद्ध जारी है और कविता हर दिन शहीद हो रही है।

एसआईआर के खिलाफ खोखले मोर्चे, बगैर एसआइआर के मतदाता सूचियों की गड़बड़ी को सही कैसे किया जा सकता है?

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के खिलाफ एक मोर्चा संसद में खुला है तो दूसरा सुप्रीम कोर्ट में। ये दोनों मोर्चे तभी खुल गए थे, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआइआर कराने का निर्णय लिया था। यह निर्णय सामने आते ही कुछ विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी की संज्ञा दे दी। उनकी और विशेष रूप से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस दलील की आड़ में दुष्प्रचार किया जाने लगा कि एसआइआर का उद्देश्य उनके समर्थकों के वोट काटना और इस तरह विधानसभा चुनावों में भाजपा की मदद करना है।

चूंकि एसआइआर को वोट चोरी बताया जाना ध्यानाकर्षण करने वाला जुमला था, इसलिए उसे जोर-शोर से तूल तो दिया जाने लगा, लेकिन यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं समझी गई कि क्या सारे बूथ लेवल आफिसर यानी बीएलओ सत्ताधारी दल के समर्थक हैं और क्या उन्हें यह पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति किस दल को वोट देता है?

बिहार में एसआइआर के दौरान एक ओर जहां कांग्रेस और राजद नेता वोटर अधिकार यात्रा निकालते रहे, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया के खिलाफ सुनवाई भी होती रही। चुनाव आते-आते बिहार के लोगों के लिए एसआइआर कोई मुद्दा ही नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआइआर में कोई खोट नहीं पाया। इसके बाद भी मानसून सत्र के दौरान संसद वोट चोरी के शोर से गुंजायमान होती रही। बिहार में एसआइआर की प्रक्रिया के तहत जब 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए तो फिर से वोट चोरी का शोर उठा, लेकिन मतदाता सूची का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद 65 लोग भी ऐसी किसी शिकायत के साथ सामने नहीं आए कि वे बिहार के नागरिक हैं, उनके पास सारे वैध दस्तावेज हैं और फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। वोट चोरी का आरोप लगा रहे विपक्षी दल भी ऐसे किसी शख्स को सामने नहीं ला सके, जिसका नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाया गया हो। इसका नतीजा यह हुआ कि वोट चोरी मुद्दे की बची-खुची हवा भी निकल गई, लेकिन विपक्षी दल अब भी यह मानकर चल रहे हैं कि 12 राज्यों में एसआइआर की जो प्रक्रिया जारी है, उसका मकसद वोट चोरी करना यानी उनके समर्थकों के वोट काटना और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत की राह आसान करना है।

जैसे बिहार में एसआइआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का ढेर लग गया था, वैसे ही 12 राज्यों में जारी इस प्रक्रिया के खिलाफ न जाने कितनी याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। याचिकाएं दायर करने वालों में तमिलनाडु, बंगाल और केरल के राजनीतिक दलों के साथ कथित लोकतंत्र हितैषी लोग और संस्थाएं हैं। उनकी ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदि मोर्चा संभाले हैं। 12 राज्यों में एसआइआर के खिलाफ दायर याचिकाओं का स्वर भी यही है कि यह एक गैर जरूरी प्रक्रिया है और चुनाव आयोग के पास इसे कराने का अधिकार नहीं।

इन याचिकाओं में भी यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जा रहा है कि विपक्ष शासित राज्यों बंगाल, तमिलनाडु, केरल के बीएलओ भी एसआइआर के दौरान भाजपा विरोधी दलों के समर्थकों के वोट काटने का काम करेंगे? इस पर गौर करें कि कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनी गई कि बीएलओ लोगों से किसी बहाने यह भी पूछ रहे हैं कि पिछली बार उन्होंने किसे वोट दिया था या फिर आगे किसे वोट देने का इरादा रखते हैं?

चूंकि सरकार संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा कराने को तैयार हो गई है, इसलिए यह आशंका दूर हो गई कि एसआइआर पर संसद का यह सत्र भी पिछले सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। यह स्वाभाविक ही है कि चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान एसआइआर पर भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार नहीं कि 12 राज्यों में जारी यह प्रक्रिया रुकने वाली है, क्योंकि एसआइआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इसी कारण उसकी प्रक्रिया बिहार में संपन्न हो सकी।

एसआइआर के विरोध का एक आधार यह है कि बीएलओ तनाव और दबाव में हैं और कुछ ने इसके चलते या तो नौकरी छोड़ दी या आत्महत्या कर ली। ऐसी खबरों को निराधार नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एसआइआर कराया ही न जाए। बीएलओ की समस्याओं का कारण यह है कि उन्हें या तो सही तरह प्रशिक्षित नहीं किया गया या फिर उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके समाधान का प्रभावी तंत्र नहीं बनाया जा सका है। उनकी एक अड़चन एप का सही तरह न चलना है।

निःसंदेह बीएलओ की समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए और इसके लिए आवश्यक हो तो एसआइआर की समयसीमा और बढ़ाई जाए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि विपक्षी दल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत भी करें और एसआइआर भी न होने दें। यदि विपक्ष यह समझता है कि एसआइआर मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों को ठीक करने का उचित उपाय नहीं तो फिर उसे यह बताना चाहिए कि सही तरीका क्या है? मौजूदा विपक्ष की समस्या यह है कि वह सरकार के साथ संवैधानिक संस्थाओं की नीयत पर शक करने की आदत से ग्रस्त हो गया है और यह एक ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज किसी के पास नहीं।

अभियान

अनादि अग्नि-स्तंभ का रहस्य और शिवलिंग की उत्पत्ति की अनंत दिव्य कथा

सृष्टि के बिल्कुल प्रारंभिक काल में, जब न समय का कोई माप था, न दिशाओं का कोई निर्धारण, जब शून्य की गोद में ब्रह्मांड नवजात शिशु की तरह धीरे-धीरे आकार ले रहा था, तब एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी — ऐसी घटना जिसने देवताओं, ऋषियों और असंख्य लोकों की चेतना को हिला दिया। ब्रह्मा और विष्णु — दो महान देवता, जो स्वयं सृष्टि और पालन के आधार थे — एक ऐसे विवाद में उलझ गए जिसकी जड़ अहंकार थी और जिसका परिणाम अकल्पनीय। ब्रह्मा कहते कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा से प्राणी, मनुष्य, प्राणी-जगत, वनस्पतियाँ, लोक—सब अस्तित्व में आए। विष्णु कहते कि मैं सर्वोच्च हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई सृष्टि टिक ही नहीं सकती। मेरी ही शक्ति से यह संसार संतुलित रहता है।

यह विवाद धीरे-धीरे सब लोकों में फैल गया। देवलोक की सभा में यह चर्चा अनवरत चलने लगी। गंधर्व आश्चर्य से भर गए, अप्सराएँ मौन हो गईं, सिद्ध और ऋषि विचार करने लगे कि क्या देवता भी इस प्रकार भूले-भटके अहंकार में पड़ सकते हैं। अंततः सभी ने यह तय किया कि इस विवाद का समाधान केवल एक ही दे सकता है — वह जो न रचना में बंधा है, न पालन में, न संहार में; वह जो समय से परे है, कारण-कार्य से परे है। वह केवल महादेव ही हो सकते हैं।

सब देवता, ब्रह्मा और विष्णु के संग कैलाश की ओर बढ़े। हिमालय की चोटियाँ मंद-मंद प्रकाश से झिलमिला उठीं, मानो शिव के ध्यान की तरंगें सम्पूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही हों। जब सब कैलाश पहुँचे, तब महादेव समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर न समय था, न काल। उनकी श्वास का उठना-गिरना भी ब्रह्मांड के कंपन जैसा शांत और असीम था। पर शिव सर्वज्ञ हैं; उन्होंने सबकी उपस्थिति का अनुभव किया और समाधि से उभरते ही उनके नेत्रों से ऐसा प्रकाश फूटा कि सभी देव झुककर उनकी स्तुति करने लगे।

देवताओं ने नम्रता से निवेदन किया कि ब्रह्मा और विष्णु के इस मतभेद को दूर करें, जो अब लोकों में अशांति का कारण बन गया है। शिव ने गहरा, गंभीर और शांत स्वर में कहा—"जिसे यह लगता है कि वह सर्वोच्च है, उसे मेरी अग्नि-ज्योति का अंतिम छोर ढूँढना होगा। जो इसकी सीमा पा लेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा।"

उनके कहते ही एक ऐसा तेज, ऐसी अग्नि, ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि किसी ने पहले कभी न देखा था। महादेव के भीतर से प्रकट हुआ वह ज्योति-स्तंभ न ऊपर खत्म होता था, न नीचे, न किसी ओर। वह अनंत था — महाकाल की धधकती चेतना जैसा, सृष्टि के केंद्र में स्थित आदिशक्ति जैसा। उसका तेज इतना था कि देवताओं की आँखें झुक गईं, और उसकी ऊँचाई इतनी कि आकाश भी नाप न सका।

विष्णु ने तुरंत कहा—"मैं पाताल की गहराइयों में जाकर इसका निचला अंत ढूँढूँगा।" और वे वराह रूप धारण कर अद्भुत वेग से अंधकारमय गहराइयों की ओर उतरने लगे। ब्रह्मा ने कहा—"मैं आकाश की ओर उड़कर इसका ऊपरी छोर ढूँढूँगा।" और वे हंस रूप धारण कर ऊपर उठते गए, बहुत ऊपर, वहाँ तक जहाँ प्रकाश के भी पंख थकने लगते हैं। विष्णु पाताल में जाते रहे — नागलोक, रसातल, तलातल, महातल — हर लोक पार करते हुए भी वह ज्योति किसी सीमा का परिचय नहीं दे रही थी। वह जितना नीचे जाते, उतनी ही दूर सरक जाती। अंत में विष्णु समझ गए कि यह अग्नि-स्तंभ अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं। वे थक गए, पर सत्य को स्वीकारने में पीछे नहीं हटे। वे लौट आए और शिव के समक्ष नतमस्तक होकर बोले—"प्रभो, आपकी ज्योति का कोई अंत नहीं। मैं सीमा तक नहीं पहुँच सका। आप ही परम हैं।"

उधर ब्रह्मा ऊपर उड़ते रहे — लोकों के पार, नक्षत्रों के ऊपर, ध्रुवों के आगे, महाशून्य में। उन्हें कोई अंतिम छोर नहीं मिला। परंतु लौटकर यह स्वीकारना उनके अहंकार को असह्य लग रहा था। तभी उन्हें एक दिव्य प्रकाशमान केतकी पुष्प दिखा। ब्रह्मा ने उससे कहा—"तुम मेरा साक्ष्य बनो कि मैं ज्योति के अंतिम छोर तक पहुँचा।" केतकी सहमत हो गया। ब्रह्मा लौटे और शिव से बोले—"मैं अंतिम छोर तक पहुँच गया हूँ। यह पुष्प मेरे साथ था।" यह सुनकर शिव का मुख शांत होते हुए भी भीतर से क्रोध से दीप्त हो गया। उन्होंने कठोर सत्य कहा—"ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा है। यह पुष्प भी असत्य में सहभागी हुआ है। इसलिए आज से न तुम मेरी पूजा में पूजित होगे, न यह पुष्प कभी मेरी उपासना में चढ़ेगा।"

उस क्षण से आज तक केतकी पुष्प शिव पूजा में वर्जित है।

इसके बाद शिव ने विष्णु की ओर देखा। विष्णु का मुख शांत, विनम्र और सत्य से ओतप्रोत था। शिव बोले—"सत्य स्वीकारने का सामर्थ्य ही वास्तविक शक्ति है। इसलिए विष्णु, तुम पूजनीय हो। तुम्हारी भक्ति फलदायी होगी।"

फिर महादेव ने उस अनंत ज्योति-स्तंभ को शांत कर स्थिर कर दिया। वही ज्योति आगे चलकर शिवलिंग कहलाया — वह चिह्न जो निराकार शिव का प्रतीक है; वह रूप जो रूपहीन है; वह प्रकाश जो किसी भी ओर से सीमाबद्ध नहीं; वह शक्ति जो ब्रह्मांड के उद्गम का रहस्य है।

शिवलिंग का अर्थ ही है — 'लिंगं, चिह्नं' — अनंत का चिह्न। ब्रह्मांड का मूल, चेतना का केंद्र, समय से रहित प्रकाश का स्तंभ।

उस दिन ब्रह्मा का अहंकार संसार को शिक्षित कर गया कि असत्य चाहे कितना आकर्षक हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। विष्णु का समर्पण यह बताता है कि विनम्रता ही देवत्व का मार्ग है। और महादेव का प्रकाश यह कहता है कि शिव वह हैं जिनका न आदि है, न अंत; जो कहीं नहीं और फिर भी हर जगह हैं; जो रूप के भी पार हैं और अरूप के भी पार।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास को गति देने वाले हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने के उपक्रम में गांधीनगर में चौथी समीक्षा बैठक आयोजित की

▸▸ 11,360 करोड़ रुपए के कुल 27 प्रोजेक्ट्स के कामकाज की समीक्षा की गई

▸▸ प्रोजेक्ट्स उनकी निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों तथा गुणवत्ता में कोई कम्प्रोमाइज न हो; यह सुनिश्चित करने का मुख्यमंत्री का सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश

-: मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षित प्रोजेक्ट्स :-

▸▸ रेलवे के 6 प्रोजेक्ट्स - 4190.96 करोड़ रुपए
▸▸ उद्योग एवं खान विभाग से जुड़े 6 प्रोजेक्ट्स – 3657.62 करोड़ रुपए
▸▸ शहरी विकास विभाग के 12 प्रोजेक्ट्स – 3511.91 करोड़ रुपए

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास को अधिक गति देने वाले 146 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के कामकाज की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठक करने का नूतन दृष्टिकोण अपनाया है।

श्री पटेल ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को गांधीनगर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कुल 11,360 करोड़ रुपए के कुल 27 प्रोजेक्ट्स के कामकाज की समीक्षा की। इन प्रोजेक्ट्स अंतर्गत रेलवे से जुड़े 4, उद्योग एवं खान विभाग से जुड़े 6 और शहरी विकास विभाग के 15 प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन तथा समीक्षा हुई। उन्होंने राज्य के ऐसे हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की सर्वग्राही समीक्षा के उपक्रमों में अब तक तीन समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में लगभग 67 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा के दौरान उनके दिए गए सुझावों के संदर्भ में सम्बद्ध विभागों द्वारा किए गए कामकाज पर भी इस चौथी समीक्षा बैठक में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत@2047 के विजन से सुसंगत विकसित गुजरात के लिए ये सभी विकासोन्मुखी हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पथदर्शक हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रोजेक्ट्स उनकी निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों तथा गुणवत्ता में कोई कम्प्रोमाइज न हो; यह सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश बैठक में दिए।

इतना ही नहीं; उन्होंने बैठक में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा कि वे रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में जमीन से सम्बद्ध मामलों के त्वरित निवारण के लिए सम्बद्ध जिला कलेक्टरों को निर्देश दें।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिन 27 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की सघन समीक्षा की; उनमें रेलवे से जुड़े 4190 करोड़ रुपए के छह प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत सामखियाळी-गांधीधाम रेलवे के चार मार्गीकरण, राजकोट-कानालुस 122 किलोमीटर लाइन की डबलिंग, नलिया तथा वयोर के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन, मोटी आदरज-वीजापुर गेज कन्वर्जन, वीजापुर-आंबलियासण गेज कन्वर्जन और नलिया-जखौ नई लाइन के प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने रेलवे अधिकारियों की उपस्थिति में राज्य में समग्रतया रेलवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की।

इसके अतिरिक्त; उन्होंने उद्योग एवं खान विभाग से जुड़े प्रोजेक्ट अंतर्गत धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट फेज-1 का डेवलपमेंट, नवसारी के पीएम मित्र पार्क में 65 एमएलडी जलापूर्ति योजना, बल्क ड्रग पार्क डेवलपमेंट, मोरबी के रफाळेश्वर के गति शक्ति कारगो टर्मिनल का निर्माण और भरूच के सायखा में 90 एमएलडी की डीप सी इफ्लुएंट डिस्पॉजिल पाइपलाइन आदि के 3657.62 करोड़ रुपए मूल्य के 6 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डीप सी इफ्लुएंट डिस्पॉजल पाइपलाइन के कार्यों को समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया।

धोलेरा एसआई के सीईओ श्री कुलदीप आर्य ने जानकारी दी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अधिकांश कार्य पूर्ण हो गया है और जेटको द्वारा 66 केवी सब स्टेशन के लिए तथा सिंचाई विभाग द्वारा उनके वर्कऑर्डर दे दिए हैं।

शहरी विकास विभाग से जुड़े 15 प्रोजेक्ट्स अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन में अहमदाबाद में 14 मेगावाट के वेस्ट टु एनर्जी प्लांट, खारीकट कैनाल डेवलपमेंट के 1 से 5 फेज, गांधी आश्रम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तथा वाडज में पीपीपी आधारित झोंपड़पट्टी पुनर्वास प्रोजेक्ट की भी बैठक में समीक्षा की गई।

इसके अलावा; जामनगर-लालपुर बाईपास जंक्शन पर फोर लेन फ्लाईओवर, सूरत महानगर में बीआरटी क्रॉसिंग पर फोर लेन फ्लाई ओवरब्रिज की प्रगति की जानकारी बैठक में दी गई।

शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन ने जूनागढ शहर के अंडर ग्राउंड ड्रैनेज प्रोजेक्ट के कामकाज का भी विवरण दिया।

इस बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, सम्बद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव, रेलवे के डीआरएम, वरिष्ठ सचिव, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह तथा मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे सहभागी हुए।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और भुज के बीच चलाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा के लिए तथा अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस – भुज स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर पूर्ण आरक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस स्पेशल ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09037/09038 बांद्रा टर्मिनस – भुज सुपरफास्ट (द्विसाप्ताहिक) स्पेशल [24 फेरे]

ट्रेन संख्या 09037 बांद्रा टर्मिनस – भुज सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 14:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05:50 बजे भुज पहुंचेगी। यह ट्रेन 06 दिसम्बर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09038 भुज – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार को भुज से 17:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 07 दिसम्बर, 2025 से 16 जनवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, ध्रांगध्रा, सामाख्याली, भचाऊ तथा गांधीधाम स्टेशनों पर ठहरेगी।

यह ट्रेन पूर्णतः आरक्षित रहेगी तथा इस ट्रेन में एसी 3-टियर कोचेस रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09037 एवं 09038 की बुकिंग 04 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्री ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में रेल अवसंरचना को नई रफ़्तार: अंबिकापुर क्षेत्र के लिए कई नई रेल लाइन परियोजनाएँ तेज़

(जीएनएस)। अंबिकापुर तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेल संपर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में रेल परियोजनाओं को अभूतपूर्व गति प्रदान की जा रही है। यह जानकारी आज लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दी। मंत्री ने बताया कि यह प्रश्न सांसद श्री चिन्तामणि महाराज द्वारा पूछा गया था। अंबिकापुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। बोरिडांड–अंबिकापुर (सुरजपुर) दोहरीकरण परियोजना (80 किमी) पर कार्य आरंभ किया जा चुका है। अंबिकापुर–रामानुजगंज–बरवाडीह नई रेल लाइन तथा रामानुजगंज–गढ़वा रोड सहायक लाइन (262 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इसी प्रकार सरडेगा–पत्थलगांव–अंबिकापुर नई रेल लाइन (218 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ के लिए रेल बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009–14 के दौरान जहाँ औसत वार्षिक आवंटन 311 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2025–26 में यह बढ़कर 6,925 करोड़ रुपये हो गया है—जो 22 गुना से अधिक वृद्धि दर्शाता है।

नया रेल लाइनों का कमीशनिंग भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। वर्ष 2009–14 के दौरान केवल 32 किमी (औसत 6.4 किमी/वर्ष) रेल लाइनें कमीशन की गई थीं, जबकि वर्ष 2014–25 के दौरान 1,189 किमी (औसत 108.1 किमी/वर्ष) रेल लाइनें कमीशन की गईं—जो 15 गुना से अधिक वृद्धि है।

01 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में आंशिक या पूर्ण रूप से स्थित कुल 26 रेल परियोजनाएँ (06 नई लाइनें और 20 दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ) 1,931 किमी लंबाई एवं 31,619 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 1,023 किमी लंबाई का कमीशनिंग पूर्ण किया जा चुका है तथा मार्च 2025 तक 16,325 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अंबिकापुर क्षेत्र सहित पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष (2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) में कुल 26 सर्वेक्षणों को, कुल 3,901 किमी लंबाई को कवर करते हुए, स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति यातायात पूर्वानुमान, लाभप्रदता, पहली–अंतिम मील कनेक्टिविटी, अपूर्ण कड़ियों को जोड़ना, मार्ग विस्तार, राज्य सरकारों एवं जनप्रतिनिधियों की माँगें, रेलवे की परिचालन आवश्यकताएँ तथा सामाजिक–आर्थिक महत्व जैसे मानदंडों पर आधारित होती है।

उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूर्ण होने का समय भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, सांविधिक अनुमतियाँ, स्थानीय स्थलाकृति, कानून-व्यवस्था तथा मौसम आधारित कार्य-दिवस जैसे कारकों से प्रभावित होता है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि अंबिकापुर क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है एवं इनके त्वरित कार्यान्वयन हेतु निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी 17 नगर निगम क्षेत्रों में रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान और सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। यह कदम राज्य सरकार की तरफ से उन विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने की कोशिश के तहत उठाया गया है, जो अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे हैं।

सरकार ने कमिश्नर और आईजी को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची तैयार कर उसे सीधे शासन को सौंपें। इसके अलावा प्रदेश के सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश भी जारी किया गया है, ताकि अवैध घुसपैठियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत रखा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

योगी सरकार के इस निर्देश के बाद नगर निकायों और शासन के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। विभिन्न जिलों में रोहिंग्या घुसपैठियों का चिन्हांकन शुरू हो गया है, और प्रशासन ने उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए व्यापक सर्वे और अभियान प्रारंभ कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि चिन्हांकन अभियान में स्थानीय पुलिस, नगर निगम और राज्य प्रशासन के संयुक्त दल शामिल हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र में जांच कर अवैध प्रवासियों की पहचान करेंगे।

राज्य सरकार का यह कदम पिछले कुछ समय से रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और उनके अवैध ठहराव की चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि डिटेंशन सेंटरों के निर्माण के बाद अवैध घुसपैठियों को कानूनी कार्रवाई और निगरानी के तहत रखा जाएगा।

जीएआरसी की छठी रिपोर्ट में डेमोग्राफिक डिविडेंड समान युवाओं को उचित मौके एवं रोजगार के अवसर देकर उनकी असीम शक्ति को विकसित गुजरात के निर्माण में जोड़ने की सिफारिशें

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट

-: छठी रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें :-

▸▸ भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए सुनिश्चित समयसीमा
▸▸ संयुक्त भर्ती तथा कॉमन सेंट्रल टेस्ट (सीईटी)
▸▸ हर दो वर्ष में निश्चित रिक्विजिशन विंडो
▸▸ संपूर्ण डिजिटल डॉक्यूमेंट वेयरीफिकेशन
▸▸ कैंडिडेट फ्रेंड्ली-एंड टु एंड डैशबोर्ड
▸▸ रिक्विजिशन से नियुक्ति तक संपूर्ण डिजिटल वर्कफ्लो
▸▸ भर्ती एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि-पुनर्गठन
▸▸ कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का व्यापक उपयोग
▸▸ 10 वर्ष का भर्ती कैलेंडर

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डेमोग्राफिक डिविडेंड समान युवाओं को उचित मौके तथा रोजगार के अवसर देकर उनकी असीम शक्ति को विकसित राष्ट्र-विकसित राज्य के निर्माण में जोड़ने के दिए गए विचार को राज्य में साकार करने का दृष्टिकोण अपनाया है। श्री पटेल ने इस उद्देश्य से राज्य सरकार के प्रशासनिक ढाँचे तथा कार्य पद्धति में आवश्यक फेरबदल के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) का गठन किया है।

इस प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को अपनी छठी सिफारिश रिपोर्ट सौंपी। जीएआरसी इससे पहले तक राज्य सरकार को पाँच रिपोर्ट सौंप चुका है।

मुख्यमंत्री को बुधवार को सौंपी गई जीएआरसी की छठी रिपोर्ट में राज्य में भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी, टेक्नोलॉजी से युक्त तथा युवा केन्द्रित बनाने की लगभग 9 सिफारिशें की गई हैं।

जीएआरसी की इस छठी रिपोर्ट में जिन मुद्दों को शामिल किया गया है, उनके अनुसार

1. भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए निश्चित टाइमलाइन

जिस भर्ती प्रक्रिया में तीन स्टेज हों, वह 9 से 12 महीने में और जिसमें दो स्टेज हों, वह 6 से 9 महीने में पूरी करने और भविष्य में इस समयावधि से भी कम समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो; ऐसी सिफारिश की गई है।

2. संयुक्त भर्ती तथा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी)

रिपोर्ट में समान शैक्षणिक योग्यता वाले विभिन्न कैडरों के लिए संयुक्त प्रिलिम्स तथा विषयवार मेन्स परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाने की सिफारिश की गई है। इससे समान प्रकार के कैडर के लिए अलग-अलग परीक्षा पर होने वाले प्रशासनिक एवं वित्तीय खर्च में काफी कमी लाकर भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सकेगी।

3. हर दो वर्ष में दो निश्चित रिक्विजिशन विंडो

हर दो वर्ष में दो निश्चित रिक्विजिशन विंडो निर्धारित कर सभी विभागों द्वारा ऑनलाइन मांगपत्र सबमिट करने की व्यवस्था के साथ भर्ती नियमों, परीक्षा नियमों और प्रशिक्षण नियमों के लिए एक केन्द्रीय सेल का गठन करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके फलस्वरूप; भर्ती प्रक्रिया के लिए आवश्यक नियमों को बहुत तेजी से अंतिम रूप दिया जा सकेगा और भर्ती प्रक्रिया तेज बनेगी।

4. संपूर्ण डिजिटल डॉक्यूमेंट वेयरीफिकेशन (आईएएसएस)

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि हाल में होने वाली मैनुअल जाँच के स्थान पर संपूर्ण डिजिटल दस्तावेज से जाँच करने से तथा डिजी-लॉकर की तरह ही एपीआई-लिंक्ड डेटाबेस और यूनिक उम्मीदवार डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री के गठन से भर्ती करने वाली संस्था और सरकारी विभागों के बीच उम्मीदवारों के दस्तावेज आसानी से भेजे जा सकेंगे और डॉक्यूमेंट वेयरीफिकेशन भी बहुत प्रभावशाली बनेगा।

5. कैंडिडेट फ्रेंड्ली-एंड टु एंड डैशबोर्ड

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उम्मीदवार आधारित यूनिक आईडी पर एंड टु एंड डैशबोर्ड बनाया जाए, जिसमें आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की समग्र प्रक्रिया को ट्रैक किए जाने सकने की व्यवस्था के साथ जिलेवार पोस्टिंग के लिए डिजिटल माध्यम से जिला चयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

6. रिक्विजिशन से नियुक्ति तक संपूर्ण डिजिटल वर्कफ्लो

एकीकृत डिजिटल पोर्टल द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स (विभागों-एजेंसियों-उम्मीदवारों) के बीच सूचना का आदान-प्रदान संभव होगा और उम्मीदवारों को एक ही प्रकार के दस्तावेज बार-बार अलग-अलग भर्ती संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिकोण के साथ एकरूपता की सिफारिश की गई है।

7. भर्ती एजेंसियों की क्षमता में वृद्धि तथा पुनर्गठन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीनस्थ विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती के लिए नए मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (एमएसआरबी) का गठन करने और जीएसएसएसबी, जीपीएसएसबी तथा जीपीआरबी को गुजरात लोक सेवा आयोग के समक्ष आवश्यक व आर्थिक स्वायत्तता देने की सिफारिश इस रिपोर्ट में हुई है।

8. कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का व्यापक उपयोग

राज्य में जहाँ तक संभव हो, परीक्षाएँ कम्प्यूटर आधारित (कम्प्यूटर बेस्ड) ली जाएँ और ऐसी परीक्षा की प्रभावी देखरेख के लिए हर भर्ती एजेंसी में एक अलग एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट (ईएमयू) की स्थापना की जाए। यह भी सुझाव रिपोर्ट में दिया गया है।

9. 10 वर्ष का भर्ती कैलेंडर

हर विभाग के लिए भावी आवश्यकताओं पर आधारित 10 वर्ष के भर्ती कैलेंडर की समीक्षा कर बहुत ही महत्वपूर्ण इमर्जेंसी सर्विस तथा क्रिटिकल कैडर की पहचान कर हर संभव तेजी से भर्ती करने की सिफारिश जीएआरसी ने की है। देश के विकास में अग्रसर गुजरात के युवाओं को तेजी से अधिक एवं प्रभावी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प को इन सिफारिशों से पूरा किया जा सकेगा।

इतना ही नहीं; जीएआरसी द्वारा की गई ये सिफारिशें लागू करने से भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष से कम समयसीमा में पूर्ण हो सके, राज्य के युवाओं को समय पर तथा पारदर्शी रोजगार के अवसर प्राप्त हों, लंबे समय से लंबित रिक्तियाँ तेजी से भरी जाएँ और सरकार की प्रशासनिक क्षमता एवं सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में गति आए; ऐसा राज्य सरकार का दृष्टिकोण साकार होगा।

मुख्यमंत्री को जीएआरसी की यह छठी रिपोर्ट सौंपे जाने के अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, प्रशासनिक सुधार प्रभाग के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और जीएआरसी के अधिकारी उपस्थित रहे।

जीएआरसी की छठी रिपोर्ट की सिफारिशें जीएआरसी की वेबसाइट https://garcguj.in/resources पर अपलोड की गई हैं।

छापरा फूड पार्क के लॉन्च के साथ गुजरात ने कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाया

▸▸ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) – राजकोट तथा कच्छ द्वारा मुख्य निवेशों की पूर्व समीक्षा : जीआईडीसी ने राजकोट फूड पार्क प्लान का अनावरण किया

▸▸ सौराष्ट्र का नया लॉजिस्टिक्स पावरहाउस : छापरा में जीआईडीसी पार्क का अनावरण

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात में औद्योगिक विकास की नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा राजकोट के छापरा गाँव में स्थापित होने वाले नए एग्रो फूड पार्क का अनावरण होने से सौराष्ट्र के कृषि उद्योग क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। यह पहल राज्य के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने तथा उल्लेखनीय निवेश आकर्षित करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक रणनीतिक कदम है। इस फूड पार्क द्वारा जीआईडीसी की औद्योगिक बस्तियों में उद्योगों की व्यवस्थित स्थापना तथा संगठन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सड़क, बिजली, पानी, भंडारण, प्रशिक्षण केन्द्रों, कल्वर्ट, ओवरब्रिज जैसी ढाँचागत सुविधाओं तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ उद्योग क्षेत्र का सुदृढ़ संगम साकार होने वाला है।

गुजरात आज देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अग्रणियों में स्थान रखता है। केला, आलू, बाजरा तथा भिंडी जैसी फसलों के कुल 20 कृषि क्लस्टर्स के साथ राज्य में कृषि उत्पादन की विशाल क्षमता है। जामनगर, द्वारका तथा पोरबंदर जैसे जिलों में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पहले से ही मजबूत उपस्थिति है। राजकोट तो फूड प्रोसेसिंग तथा उससे जुड़े उद्योगों के लिए जाना-माना केन्द्र है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बालाजी वेफर्स ने गुजरात के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में छापरा की नई वेस्ट टु एनर्जी प्लांट, खारीकट कैनाल डेवलपमेंट के 1 से 5 फेज, गांधी आश्रम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तथा वाडज में पीपीपी आधारित झोंपड़पट्टी पुनर्वास प्रोजेक्ट की भी बैठक में समीक्षा की गई।

इसके अलावा; जामनगर-लालपुर बाईपास जंक्शन पर फोर लेन फ्लाईओवर, सूरत महानगर में बीआरटी क्रॉसिंग पर फोर लेन फ्लाई ओवरब्रिज की प्रगति की जानकारी बैठक में दी गई।

शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन ने जूनागढ शहर के अंडर ग्राउंड ड्रैनेज प्रोजेक्ट के कामकाज का भी विवरण दिया।

इस बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, सम्बद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव, रेलवे के डीआरएम, वरिष्ठ सचिव, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह तथा मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे सहभागी हुए।

प्रोजेक्ट की झाँकी तथा स्थान के लाभ

छापरा में 35 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किए जाने वाले फूड पार्क को सौराष्ट्र के नए लॉजिस्टिक्स पावरहाउस के रूप में देखा जा रहा है। उसकी भौगोलिक स्थिति उद्योग क्षेत्र के लिए अनेक सुविधाओं के साथ वरदान स्वरूप है। राज्य राजमार्ग के निकट होने के कारण आंतरिक परिवहन सरल रहता है, जबकि राजकोट रेलवे स्टेशन तथा हीरापर हवाई अड्डे की निकटता उद्योगों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी उलब्ध कराती है। इस फूड पार्क का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के निकट होना संचालन को अधिक तेज व कार्यक्षम बनाता है। कंडला जैसे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण निर्यात आधारित उद्योगों के लिए भी इस पार्क के एक रणनीतिक स्थान बनने की संभावना है।

निवेश की संभावनाएँ

मुख्य ढाँचागत सुविधाएँ

जीआईडीसी द्वारा पार्क में औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें सुव्यवस्थित आंतरिक सड़क व्यवस्था, पेयजल, निरंतर विद्युत आपूर्ति तथा गैस पाइपलाइन जैसी मूलभूत सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अलावा; एडमिन कॉम्प्लेक्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी), स्ट्रीट लाइटिंग जैसी व्यवस्थाएँ पार्क को हर जरूरत को पूरा करेंगी। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण हमेशा प्रमुख फैक्टर होता है। इसके अनुरूप यहाँ वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ उत्पादन, रखरखाव तथा आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कार्यक्षम बनाएंगी।

गुजरात सरकार ने निवेश आकर्षित करने, टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने तथा आजीविका आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। मुडेथा (बनासकाँठा) और छापरा (राजकोट) स्थित प्रोजेक्ट्स इस रणनीति का मुख्य हिस्सा हैं और सामूहिक रूप से 500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का उद्देश्य है। इस निवेश से लगभग 30,000 प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। 8 व 9 जनवरी, 2026 को राजकोट में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय परिषद् (वीजीआरसी) समग्र खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने तथा कच्छ एवं राजकोट जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए सहयोगी इकोसिस्टम स्थापित करने के एक गतिशील प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा देगी।

प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान: प्राकृतिक खेती से किसानों की आय, मिट्टी की सेहत और पर्यावरण की रक्षा में क्रांतिकारी बदलाव संभव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशभर के किसानों और आम जनता से प्राकृतिक खेती अपनाने और इसे बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक लिंक्डइन अकाउंट पर एक विस्तृत लेख साझा किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में कोयंबटूर, तमिलनाडु में आयोजित साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 में अपने अनुभवों और प्राकृतिक खेती के महत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल किसानों की लागत कम करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, जैव विविधता को संरक्षित करने और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में उल्लेख किया कि उन्होंने कुछ महीने पहले तमिलनाडु के किसानों के एक समूह से मुलाकात की थी, जिन्होंने प्राकृतिक खेती के नवाचारी और पारंपरिक तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। किसानों के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री 19 नवंबर को कोयंबटूर में इस सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से एमएसएमई हब माने जाने वाले कोयंबटूर में प्राकृतिक खेती पर इतना बड़ा आयोजन, कृषि जगत में नई सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने लिखा कि प्राकृतिक खेती भारत की प्राचीन कृषि परंपरा और आधुनिक पारिस्थितिक विज्ञान का मिश्रण है। इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता और फसल, पेड़ और पशुधन को सहजीवी रूप से विकसित होने दिया जाता है। इस प्रणाली में खेत के अवशेषों का पुनर्चक्रण, मल्चिंग और प्राकृतिक पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और दीर्घकालिक उर्वरता में सुधार होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में मिले किसानों और कृषि नवप्रवर्तकों की प्रेरक कहानियों का उदाहरण देते हुए बताया कि युवा वैज्ञानिक, एफपीओ प्रमुख और पहले कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम कर चुके लोग अब प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक किसान 10 एकड़ भूमि पर केले, नारियल, पपीता, काली मिर्च और हल्दी की मल्टी-लेयर फार्मिंग के साथ 60 देशी गायें, 400 बकरियां और देसी मुर्गीपालन चला रहे हैं। वहीं कुछ किसान देशी धान किस्मों को संरक्षित कर मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर रहे हैं। एक प्रथम पीढ़ी का युवा किसान 15 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करके 3,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दे चुका है और हर महीने 30 टन सब्जियों की आपूर्ति कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत सरकार ने लाखों किसानों को इससे जोड़ते हुए हजारों हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कर्ज सुविधा और निर्यात प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के माध्यम से पशुपालन और मत्स्य पालन तक को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चेताया कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता से मिट्टी की नमी, उर्वरता और दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हुई है, जबकि प्राकृतिक खेती इस चुनौती का स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है।

प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे छोटे स्तर पर 'एक एकड़, एक सीजन' फार्मूला अपनाकर शुरुआत करें। सकारात्मक परिणाम मिलने पर इसे बड़े पैमाने पर अपनाने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि किसान एफपीओ के माध्यम से जुड़ें या इस क्षेत्र में स्टार्टअप स्थापित करें। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में देखा गया संगम—किसानों, विज्ञान और उद्यमिता का मिलन—भारत की कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को नई दिशा देगा और देश के कृषि भविष्य को स्थायी और लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

चक्रवाती तूफान 'दित्वा' तमिलनाडु–पुडुचेरी तट के बेहद करीब, कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त; पुडुचेरी के सभी स्कूल आज बंद

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दक्षिण भारत का समुद्री तट एक बार फिर भय और अनिश्चितता के माहौल से गुजर रहा है, क्योंकि चक्रवाती तूफान 'दित्वा' तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों के बेहद करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान फिलहाल कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि पुडुचेरी से लेकर चेन्नई, कडलूर, विलुपुरम और मदुरै तक कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनज़र सभी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और समुद्र तटों से दूर रहें।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताज़ा अपडेट के अनुसार, दित्वा अब गहरे दबाव में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी इसका असर काफी बड़ा है। यह पश्चिम-मध्य और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है और लगभग तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर तमिलनाडु–दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है। तूफान का केंद्र फिलहाल तट से केवल 25 किलोमीटर दूर है, जिससे अगले कुछ घंटों में और ज्यादा बारिश तथा तेज़ हवाओं की संभावना बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि दित्वा का कमजोर होना राहत की बात जरूर है, लेकिन चक्रवात के बाद विकसित होने वाली दबाव प्रणाली कई बार उतना ही भारी जलप्रवाह और भूस्खलन उत्पन्न कर देती हैं जितना एक पूर्ण विकसित तूफान करता है। तमिलनाडु के तटीय जिलों में बारिश का प्रभाव कल रात से ही दिखने लगा था। चेन्नई के कई हिस्सों में हल्की बारिश से शुरुआत हुई, जबकि मदुरै जैसे शहरों में पूरी रात तेज़ बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया। दक्षिण मासी स्ट्रीट और आसपास के बाजारों में जलभराव के कारण दुकानें बंद करनी पड़ीं और लोग सुबह से ही अपने घरों में कैद होकर रहे। मरीना बीच और महाबलीपुरम के समुद्री किनारों पर ऊँची लहरें उठती देखी गईं। स्थानीय मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है और तट रक्षक दल लगातार गश्त कर रहा है।

पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ए. नामचिवायम ने देर रात घोषणा की कि सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखा जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने सुबह से दोपहर तक तेज़ बारिश और कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की आशंका जताई है। प्रशासन ने बचाव दल, दमकलकर्मियों और आपदा प्रबंधन बल को अलर्ट पर रखा है। कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें मिली हैं, जिससे जीवन की दैनिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ा है। लोग अपने घरों के आस-पास से पानी निकालने के लिए नगरपालिका कर्मियों की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं और कई स्थानों पर सड़कें बंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना रोकी जा सके।

तूफान के आगे बढ़ने की दिशा को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 24 घंटे दक्षिण भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है और स्थानीय प्रशासन को व्यापक स्तर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। फिलहाल सभी नज़रें आसमान की ओर हैं, जहां काले बादल लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि दित्वा भले कमजोर हो चुका हो, लेकिन उसका असर अब भी उतना ही शक्तिशाली है कि पूरे क्षेत्र के जनजीवन को थाम दे।

ज्ञानवापी वजूखाने के ताले का पुराना कपड़ा बदलेगा या नहीं, 15 दिसंबर को आएगा फैसला

(जीएनएस)। वाराणसी। वाराणसी में शृंगार गौरी–ज्ञानवापी प्रकरण की गहमागहमी के बीच सील वजूखाने के ताले पर लगे पुराने और जर्जर कपड़े को बदलने के संबंध में बुधवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले में जिला जज संजीव शुक्ला ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही "पूजा स्थल उपबंध विधेयक 1991" से जुड़े मामलों का असर निचली अदालतों में भी पड़ा है। अदालत ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2025 को निर्धारित की, जब इस मामले में ताले के कपड़े बदलने या न बदलने का अंतिम निर्णय आने की संभावना है।

वादी पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 12 दिसंबर को स्पष्ट निर्देश दिया था कि पूजा स्थल उपबंध विधेयक 1991 से जुड़े मामलों में निचली अदालतों में किसी भी नए आदेश की अनुमति नहीं होगी, ताकि शीर्ष अदालत की सुनवाई प्रभावित न हो। इसी आधार पर जिला अदालत ने इस मामले में फिलहाल किसी भी बदलाव को रोकते हुए अगली तारीख पर फैसला सुरक्षित रखा। शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने ताले में लगे पुराने कपड़े बदलने की अर्जी पर नॉटप्रेस (अस्थायी स्थगन) का अनुरोध किया है और इसे जिला जज द्वारा सुनवाई के दौरान आदेशित किया जाएगा।

इस मामले में प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने पिछले अवसर पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि बिना सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के मार्गदर्शन के किसी भी बदलाव को मंजूरी देना उचित नहीं है। अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट और जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, जिलाधिकारी वाराणसी को नियंत्रक नियुक्त किया गया है, ताकि ताले के कपड़े में बदलाव या सुधार करते समय किसी भी पक्ष की आपत्ति न आए और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।

पिछली सुनवाई में वादी पक्ष ने ताले के जर्जर और पुरानी स्थिति वाले कपड़े बदलने की अनुमति देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि कपड़े का जर्जर होना सुरक्षा और धार्मिक अनुष्ठान दोनों के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने यह तर्क दिया कि पुराने कपड़े पर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का असर पड़ सकता है और बदलाव बिना उचित अनुमोदन के नहीं होना चाहिए। अदालत ने सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल किसी भी कार्रवाई को रोकते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की।

वाराणसी की जनता, धार्मिक समुदाय और न्यायिक विशेषज्ञ इस मामले पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। हर कोई 15 दिसंबर 2025 को आने वाले फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। इस मामले का निर्णय न केवल ज्ञानवापी परिसर की धार्मिक प्रथाओं के लिए अहम होगा, बल्कि यह भविष्य में पूजा स्थल उपबंध विधेयक 1991 से जुड़े अन्य मामलों में भी दिशा-निर्देश का काम कर सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया, नए श्रम कानूनों पर मांगा जवाब

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

याचिका वकील एन.ए. सेबेस्टियन और सुनील कुमार की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस. गरिया ने अदालत को बताया कि 29 से अधिक पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर 21 नवंबर 2025 को चार नए श्रम कानून लागू किए गए हैं। इन कानूनों के तहत पुराने लेबर कोर्ट को समाप्त कर लेबर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना था। लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार, ट्रिब्यूनल का गठन अभी तक नहीं हुआ है और नियम भी तैयार नहीं किए गए हैं, जिससे कानून की व्यावहारिक रूप से प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। गरिया ने अदालत को बताया कि ये नए कानून 2020 में संसद द्वारा पारित किए गए थे, लेकिन पिछले पांच सालों में सरकार नियम और अवसंरचना तैयार करने में असफल रही। इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने प्रचार-प्रसार के साथ इन कानूनों को हड़बड़ी में लागू कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन कानूनों से स्थायी रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं और यह श्रमिक विरोधी हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि नए कानूनों पर अस्थायी रोक लगाई जाए, ताकि कर्मचारियों और उद्योगों को होने वाले संभावित नुकसान को रोका जा सके।

गुजरात सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग, गुजरात सरकार के अंतर्गत

९०००से अधिक नव-नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के रूप में चयनित उम्मीदवारों को

माननीय मुख्यमंत्री

श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के

करकमलों द्वारा

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम

तारीख: ०४-१२-२०२५ | समय: सुबहः १०:३० बजे | स्थान: महात्मा मंदिर, गांधीनगर

प्रेरक उपस्थिति

डॉ. मनीषा वकील

माननीय राज्यमंत्री, महिला एवं बाल कल्याण (स्वतंत्र प्रभार),

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (राज्य कक्षा)

अब ICDS सेवाएँ

अधिक प्रभावी व मजबूत बनेंगी

बच्चों, गर्भवती माताओं, धात्री माताओं और किशोरियों के लिए पोषण,स्वास्थ्य और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास

विशेष उपस्थिति

श्रीमती मीरा पटेल
माननीय मेयर, गांधीनगर महानगरपालिका

श्रीमती शिल्पाबेन पटेल
माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत, गांधीनगर

श्री लक्ष्मणजी ठाकोर
माननीय विधायक (कलोल), गांधीनगर

श्री जयंतीभाई पटेल
माननीय विधायक (माणसा), गांधीनगर

श्री बलराजसिंह चौहान
माननीय विधायक (दहेगाम), गांधीनगर

श्री अल्पेश ठाकोर
माननीय विधायक (गांधीनगर दक्षिण), गांधीनगर

श्रीमती रीटाबेन पटेल
माननीय विधायक (गांधीनगर उत्तर), गांधीनगर

"सब साथ मिलकर गुजरात के बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के सपने को साकार करें।"

- श्री हर्ष संघवी,
माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण: CMOGujarat CMOGujarat CMOGujarat CMOGujarat